डाक पंजीयन संख्या- म.प्र./भोपाल/4-231/2023-25,
प्रकाशन प्रति सप्ताह बुधवार, पोस्टिंग प्रति सप्ताह गुरुवार
पता-म.न. 31, सेक्टर-1, शक्तिनगर, भोपाल, पिन-462024
फोन नं.-0755-4289655

MPHIN/2009/27464

साप्ताहिक
मंथन दृष्टि

प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों का समावेश

अमृत वचन
वाणी मधुर हो तो सब वश में हो जाते हैं। वाणी कटु हो तो सब शत्रु हो जाते हैं।
लोकोक्ति

नए लुक में बेटी पलक से ज्यादा जवान लगीं 44 साल की श्वेता तिवारी, फिटनेस.... पेज- 7

वर्ष : 16 अंक : 51 भोपाल: बुधवार, 02 जनवरी 2025 से 08 जनवरी 2025 पृष्ठ 8, मूल्य 5 रुपए

दिल्ली विधानसभा चुनाव बीजेपी अपने चुनावी प्रदर्शन में सुधार की कोशिश कर रही है, कांग्रेस की कोशिश 2015 और 2020 की हार से उबरने की है

आरएसएस करेगा दिल्ली में खेला! बढ़ गई केजरीवाल की टेंशन, चुपचाप इस काम को अंजाम दे रहा संघ

दिल्ली के गली-मोहल्लों में बैठक कर रही आरएसएस, केजरीवाल ने भाजपा की नीतियों को आरएसएस के विचारों के विपरीत बताया था

● मंथन संवाददाता

नई दिल्ली। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में सक्रिय रहा आरएसएस अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस चुका है। अपनी कार्यपद्धति के अनुरूप आरएसएस गली-मुहल्लों में छोटी-छोटी बैठकों का आयोजन कर रहा है, जिसमें औसतन 10-15 लोग उपस्थित होते हैं।

केजरीवाल ने आरएसएस को लिखा पत्र

आरएसएस का लक्ष्य चुनाव के पहले लगभग पांच लाख ऐसी बैठकें करने का लक्ष्य है, अभी तक एक लाख से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। माना जा रहा है आरएसएस की इन बैठकों की वजह से भाजपा को मिलने वाले फायदे की आशंका को देखते हुए ही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सर संघचालक मोहन भागवत को पत्र लिखा है। जिसमें केजरीवाल ने सवाल उठाया था कि आरएसएस भाजपा की इन नीतियों का समर्थन करता है या नहीं। वहीं, केजरीवाल के सियासी पत्र को नजरअंदाज कर आरएसएस अपने काम में लगा हुआ है।

मोहल्लों में बैठक कर रही आरएसएस

बिना झंडा-बैनर और बिना शोर-शराबे के स्वयंसेवकों के घरों में हो रही इन बैठकों के बारे में बाहरी लोगों को पता भी नहीं चलता। लेकिन संबंधित मोहल्ले के स्वयंसेवकों को पहले से इसकी सूचना होती है। बैठक में सीधे तौर पर भाजपा के लिए मतदान के लिए नहीं कहा जाता है, लेकिन दिल्ली की मौजूदा हालात का आकलन किया जाता है और राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और सामाजिक कार्यों को देखते हुए उम्मीदवार को वोट देने को कहा जाता है।

भाजपा और आरएसएस के बीच समन्वय बढ़ाने की भी कवायद

बैठक में मोहल्ले के सभी स्वयंसेवकों और आरएसएस से जुड़े परिवारों की सूची भी तैयार हो रही है, ताकि मतदान के दिन उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करायी जा सके। इसके साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा और आरएसएस के बीच समन्वय बढ़ाने की भी कवायद चल रही है। इस सिलसिले में दिसंबर के तीसरे हफ्ते में दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और प्रदेश प्रभारियों के साथ आरएसएस के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई थी। बैठक में आरएसएस के सह सरकार्यवाह और भाजपा के प्रभारी अरुण कुमार भी मौजूद थे।

15 सीटों पर 'आप' बीजेपी और कांग्रेस के बीच होगा त्रिकोणीय मुकाबला?

आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। पिछली दो चुनावों में जबरदस्त प्रदर्शन के बाद, 'आप' इस बार भी जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। भाजपा अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश में है और कांग्रेस अपनी खोई जमीन वापस पाने की उम्मीद कर रही है। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों में 'आप', बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है। 'आप' पिछले दो चुनावों में जीत हासिल कर चुकी है, जबकि बीजेपी अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश में है। कांग्रेस, जिसने 2015 और 2020 में 'आप' के हाथों अपनी जमीन गंवा दी थी, दिल्ली की राजनीति में फिर से पैर जमाने की कोशिश कर रही है।

क्या कहता है तीनों पार्टियों का रिपोर्ट कार्ड?

आम आदमी पार्टी ने पिछले दो विधानसभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन किया है। 2015 में, 'आप' ने 70 में से 67 सीटें जीतीं और 54.6 प्रतिशत वोट हासिल किए। 2020 में, पार्टी को 62 सीटें मिलीं और वोट शेयर थोड़ा कम होकर 53.6 प्रतिशत रह गया। भारतीय जनता पार्टी 2013 में 32 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। हालांकि, 2015 में उसकी सीटें घटकर केवल तीन रह गईं, जबकि 2020 में वह 8 सीटें जीतने में कामयाब रही। कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले कुछ चुनावों में लगातार खराब रहा है। 2008 में 43 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 2013 में 24.6 प्रतिशत वोट शेयर के साथ 8 सीटों पर सिमट गई। 2015 और 2020 में पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई।

15 सीटों पर होगा कड़ा मुकाबला

इस बार 'आप' और बीजेपी उन सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं जहां उन्हें पहले भारी समर्थन मिला था। साथ ही, वे उन सीटों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही हैं जहां जीत का अंतर कम था। पिछले चुनाव में 15 ऐसी सीटें थीं जहां जीत का अंतर 10,000 से कम था। 2015 में ऐसी केवल 6 सीटें थीं। 26 सीटों पर जीत का अंतर 10,001 से 20,000 वोटों के बीच था, जबकि 14 सीटों पर यह अंतर 20,001 से 30,000 वोटों के बीच था। 15 सीटों पर जीतने वाले उम्मीदवार को अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से 30,000 से अधिक वोट मिले, और ये सभी सीटें 'आप' ने जीतीं।

जिन सीटों पर जीत का अंतर कम था, वहां होंगे चौंकाने वाले नतीजे

एक वरिष्ठ 'आप' पदाधिकारी ने कहा, 'पिछले चुनाव में जिन सीटों पर जीत का अंतर 10,000 से कम था, वहां किसी भी पार्टी की जीत हो सकती है। इसलिए, चुनाव प्रचार और वादों के अलावा, बूथ स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से किया गया काम बहुत महत्वपूर्ण है।' उन्होंने आगे कहा, 'पार्टी नेतृत्व बूथ स्तर पर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संपर्क में है ताकि हमारे उम्मीदवारों को अधिकतम वोट मिलें।' -शेष पृष्ठ 2 पर

मंथन दृष्टि

पृष्ठ 2 — मतभेद — यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा नष्ट करने को...
पृष्ठ 3 — धर्म और आध्यात्म — लोहड़ी मकर संक्रांति से बहुत करीब से जुड़ा हुआ त्यौहार
पृष्ठ 4 — किसानों की सक्सेस स्टोरी मंथन — किसान पवन लोधी ने गेहूं की सीधी बुवाई पद्धति को अपनाकर 30 प्रतिशत...
पृष्ठ 5 — कृषि मंथन — एरोपोनिक तकनीक से उगाएं आलू कम लागत में होगा तगड़ा...
पृष्ठ 6 — देश-विदेश — दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का बड़ा...
पृष्ठ 7 — अनोखी खबरें — उत्तराखंड राज्य का विश्व प्रसिद्ध भगवान श्रीकृष्णजी...
पृष्ठ 8 — ख़ास साप्ताहिक फोटो — उत्तराखंड राज्य का विश्व प्रसिद्ध भगवान श्रीकृष्णजी...

दिल्ली से महाराष्ट्र तक युद्धस्तर पर अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन, गिरफ्तार कर भेजा जा रहा वापस

अवैध रूप से भारत में घुसे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक एक्शन जारी है। इस बीच महाराष्ट्र एटीएस ने सूबे के कई जिलों में रेड की और अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। वहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर उन्हें वापस भेजा जा रहा है। अभी हाल ही में 8 लोगों को बांग्लादेश भेजा गया है। महाराष्ट्र एटीएस ने 9 अवैध बंग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जिनके ऊपर 5 एफआईआर दर्ज की गई है। दिसंबर महीने में ही एटीएस ने कुल 19 एफआईआर अवैध बंगलादेशियों के खिलाफ दर्ज की हैं और 43 लोगों को गिरफ्तार किया है। नववर्ष की पूर्व संध्या पर बिना आधिकारिक पहचान पत्र के रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ स्पेशल ड्राइव में 9 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। दरसअल, एटीएस ने मुंबई के पूर्वी उपनगर विक्रोली सहित महाराष्ट्र के नाशिक,अकोला, नांदेड़ औरंगाबाद में चार दिन से सर्च ऑपरेशन चला रही थी, जिसमें उसे सफलता मिली है। गिरिफ्तार आरोपियों पर अवैध रूप से भारत में दाखिल होने सहित फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के आरोप हैं। इनके पास पुलिस को फर्जी आधार कार्ड से लेकर मतदान पत्र तक मिले हैं।

दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेश वापस भेजे अवैध नागरिक: डीसीपी साउथ दिल्ली अंकित चौहान ने बताया था कि अभियान के तहत बांग्लादेश से आए 8 अवैध प्रवासियों को पकड़ा गया। वे अपने साथ बांग्लादेशी पहचान पत्र रखे हुए थे। कुछ निर्माण स्थलों पर काम कर रहे हैं, जबकि कुछ ब्यूटी पार्लर में अपना नाम दर्ज कराने की प्लानिंग कर रहे थे। आगे की जांच के बाद उन्हें विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के माध्यम से निर्वासित कर दिया गया।

ढाका के शहीद मीनार पर छात्रों का फिर जमावड़ा, क्या बदला जाएगा बांग्लादेश का नाम और संविधान?

बांग्लादेश में जिन छात्रों ने शेख हसीना का तख्तापलट कर उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। छात्रों के आगे मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार भी घुटने टेकते नजर आ रही है। संगठन के सदस्य सचिव आरिफ सोहेल ने कार्यक्रम की घोषणा करते हुए आम जनता से इसमें भाग लेने का आग्रह किया। दावा किया जा रहा है कि संविधान बदलने से पहले बांग्लादेश का नाम बदला सकता है। छात्र संगठन देश का नया नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, इस्लामिक ऑफ बांग्लादेश और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईस्ट पाकिस्तान में से कोई एक नाम रखना चाह रहे हैं। सबसे ज्यादा संभवना यह है कि नाम बदलने की सूरत में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश के नाम पर सहमति बन सकती है।

सरकार और आंदोलनकारी छात्रों में नहीं बनी सहमति

बांग्लादेशी मीडिया ने सूत्रों के हवाले से कहा कि देश में शरिया कानून लागू किया जा सकता है। मुहम्मद युनूस को नया राष्ट्रपति घोषित किया जा सकता है। आर्मी चीफ और देश के राष्ट्रपति से इस्तीफा मांगा जा सकता है ताकि छात्र अपने मनमुताबिक देश का नया संविधान लागू करवा सकें। इससे पहले राष्ट्रीय नागरिक समिति के कई नेताओं और छात्रों के बीच बैठक हुई। सरकार ने छात्रों को प्रदर्शन न करने को कहा। हालांकि छात्र संगठन प्रदर्शन करने पर अड़े हुए हैं।

पैंगोग झील के किनारे मराठा इन्फैंट्री ने लगाई शिवाजी की मूर्ति, स्थानीय नेताओं ने क्यों जताई चिंता

लेह। 26 दिसंबर को पूर्वी लद्दाख में 14,300 फीट की ऊंचाई पर पैंगोंग त्सो झील के तट पर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। इस प्रतिमा का अनावरण मराठा इन्फैंट्री के अधिकारियों द्वारा किया गया था। इसके उद्घाटन के बाद से ही लद्दाख में बहस छिड़ गई है और कुछ स्थानीय नेता इस कदम पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि, लेह के चुशुल क्षेत्र के पार्षद और लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय परिषद (लेह) के सदस्य खोंचोक स्टैनज़िन ने प्रतिमा की स्थापना पर असंतोष व्यक्त किया। राजनीतिक कार्यकर्ता सज्जाद कारगिल्ली ने कहा कि लद्दाख में श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की कोई सांस्कृतिक या ऐतिहासिक प्रासंगिकता नहीं है। हम उनकी विरासत का सम्मान करते हैं, लेकिन यहां ऐसे सांस्कृतिक प्रतीकों को थोपना गलत है। इसके बजाय उन्होंने सुझाव दिया कि लद्दाख के लोग ख्री सुल्तान चो या अली शेर खान आंचेन और सींगे नामग्याल जैसी स्थानीय ऐतिहासिक हस्तियों के सम्मान में मूर्तियों की स्थापना की सराहना करेंगे।

✓ हमारा ''मंथन दृष्टि'' साप्ताहिक समाचार पत्र समूची दुनिया में रह रहे हिंदी भाषी भारतीयों के लिए अभी On-line पढ़ने के लिए नि:शुल्क (फ्री) उपलब्ध है। इस E-paper को पढ़ने के लिए www.manthandrishti.com पर जाएं।